



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1998/पौष 15, 1919

No. 3]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1998/PAUSA 15, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1998

अन्तिम निष्कर्ष

विषय : डेनमार्क से कुछेक कैटेलिस्टो के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच-अंतिम निष्कर्ष ।

एडीडी/डब्ल्यू/39/95-96 :—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए ।

क. क्रिया विधि

1. निम्नलिखित क्रिया विधि अपनाई गई है :—

- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इन्हें प्राधिकारी भी कहा जाएगा) ने दिनांक 7 मई, 1997 को अधिसूचना सं. द्वारा ए डी डी/आई डब्ल्यू/39/95-6 प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया तथा इच्छुक पार्टियों से अनुरोध किया कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं ।
- (2) प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजते समय सभी ज्ञात इच्छुक पार्टियों को पत्र की तारीख के 40 दिन के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था ।
- (3) प्राधिकारी ने नई दिल्ली में डेनमार्क के दूतावास को भी प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी कि डेनमार्क में निर्यातक तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत की सलाह दी जाए ।
- (4) प्राधिकारी ने 8 जुलाई, 1997 को मौखिक रूप से सुनवाई की । मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाली सभी पार्टियों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप में व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें । पार्टियों को सलाह दी गई कि विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और उनके प्रत्युत्तर खंडन प्रस्तुत करें ।

- (5) उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधारों की जानकारी ज्ञात सभी इच्छुक पार्टियों को दी गई तथा उन पर टिप्पणियां मांगी गईं, जिन पर विधिवत विचार भी कर लिया गया है ।
- (6) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा प्राधिकारी को दिए गए सभी साक्ष्यों के गैर-गोपनीय रूपांतर वाली सरकारी फाइल सभी इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध कराई । जिन पार्टियों ने उक्त फाइल के निरीक्षण के लिए लिखित अनुरोध किया था, इन्हें सरकारी फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी ।
- (7) केन्द्रीय सरकार द्वारा 17 दिसम्बर, 1997 को नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति के बाद सभी हितबद्ध पार्टियों को 22 दिसम्बर, 1997 के पत्र द्वारा सलाह दी गई थी कि यह बताएं कि क्या वे नियम 6(6) के अनुसार उनके द्वारा किए गए अनुरोधों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना चाहेंगे जो उन्होंने पहले ही लिखित में दिए हैं । इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था कि यदि वे चाहें तो अपने मामले को मौखिक रूप से स्पष्ट करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष 2 जनवरी, 1998 को उपस्थित हो सकते हैं ।
- (8) प्राधिकारी ने 2 जनवरी, 1998 को मौखिक सुनवाई की । यह स्पष्ट किया गया था कि कोई नए मामले नहीं उठाए जाएंगे और वे तक 8 जुलाई, 1998 को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए मामलों तक ही सीमित होंगे । इस बारे में कोई लिखित में ब्यौरे नहीं लिए गए ।
- (9) 2 जनवरी, 1998 को एच टी ए एस के लिए विद्वान वकील यह जानना चाहते थे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने समय-वृद्धि के लिए मंजूरी दी है । 2 जनवरी, 1998 को उपस्थित सभी हितबद्ध पार्टियों को स्पष्ट कर दिया गया था कि प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई समय-सीमाओं के भीतर ही मौखिक रूप से सुनवाई करेंगे ।
- (10) केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 जनवरी, 1998 तक दी गई समय-सीमा के भीतर ही जांच पूरी हो गई है ।

#### ख. याचिकाकर्ता के विचार

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए :

- (क) आंतरिक बाजार में बिक्री के अभाव में विचार किए जाने योग्य उपयुक्त कीमत वह होगी जो कीमत यूरोपीय संघ में निर्यातक ने ली थी ।
- (ख) प्राधिकारी द्वारा ई.यू. को एक क्षेत्र के रूप में मानना उपयुक्त है । ई. यू. के क्षेत्र मानना उपयुक्त है जो कि वास्तव में अर्द्ध-स्वायत्त इकाई है, जिसके गठन में यह व्यवस्था है कि इसकी अपनी सीमाओं के भीतर वस्तुओं का मुक्त प्रवाह है और इसके पास बाधाओं को प्रत्यक्ष रूप से दूर करने की शक्ति है और जो अब एक सांझा करेंसी पर विचार कर रहे हैं और निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखते हुए :
  - \* डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद XII में कोई भी देश अथवा अलग सीमाशुल्क क्षेत्र कवर होता है;
  - \* ई.यू. को विभिन्न प्रयोजनों के लिए एकल इकाई के रूप में माना जाता है जैसे ई.यू. को स्वयं एक सदस्य के रूप में माना जाता है । डब्ल्यू टी ओ करार के अनुबंध 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ प्रयोजनों अथवा कुछेक समीक्षाओं के लिए ई. यू. को एक ही गिना जाएगा;
  - \* सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कानून के मामले पर विचार करते समय कानून के उपबंधों की प्रयोजन मूलक व्याख्या के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए ।
  - \* यह संविधि केन्द्रीय सरकार को भारतीय उद्योग की रक्षा करने के लिए वित्तीय लेवी लगाने का अधिकार देती है अतः निर्धारित कर एक या अन्य तरीका अपनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है ।
  - \* "क्षेत्र" की अधिव्यक्ति को किसी देश में निहित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है तथा भारत के संविधान से की गई व्याख्या उपयुक्त नहीं होगी इस शब्द के लिए सार्वभौमिक अर्थ का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होगा और इस शब्द का प्रयोग इसके संदर्भ में किया जाना चाहिए अलग से नहीं ।
  - \* कानून के ये उपबंध गाट संधि का प्रत्यक्ष परिणाम हैं जिनका उद्देश्य निर्यात कीमत के साथ तुलना के लिए घरेलू कीमत को निर्धारित करना था । ई. यू. एक सहचारी इकाई है और इसे अनेक प्रयोजनों के लिए एकल इकाई के रूप में माना जाता है ।
- (ग) एच टी ए एस द्वारा ई. यू. में तथा भारतीय ग्राहकों से चार्ज की गई कीमत से यह सिद्ध होता है कि इसने भारत में कैटेलिस्ट का पाटन किया है ।
- (घ) अन्य यूरोपीय विनिर्माताओं द्वारा चार्ज की गई कीमत से भी यह पता चलता है कि निर्यातक ने भारत में कैटेलिस्ट का पाटन किया है ।
- (ङ) एच टी ए एस द्वारा की गई डम्पिंग से भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । भारतीय उद्योग उत्पादन की लागत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा था जिससे क्षमता के उपभोग को नुकसान हुआ ।

## ग. निर्यात को, आयातकों, तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

निर्यातक, हालदर टॉपसे ए/एस (जिन्हें इसके बाद एच टी ए एस कहा जाएगा) द्वारा व्यक्त किए गए विचार तथा प्राधिकारी की स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है :

- (क) प्राधिकारी से डंपिंग मार्जिन का आकलन करने में प्रयुक्त किए गए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था ।
- (ख) यह निष्कर्ष निकालना कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ई.यू. एक निर्यातक क्षेत्र हैं निम्नलिखित की दृष्टि से कानूनी रूप से सही नहीं है :
  - (i) प्राधिकारी ने न तो प्रारंभिक अधिसूचना में और न ही प्रश्नावली (सूचना के लिए अनुरोध) में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ई.यू. को घरेलू बाजार के रूप में मानने का प्रस्ताव किया है । प्राधिकारी ने नोटिस किए बिना निर्धारण करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है ।
  - (ii) एच टी एस ने डेनमार्क को निर्यातक देश के रूप में माना है और यह निवेदन किया है कि घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं हुई है । अतः निर्यातक ने उत्पादन की लागत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत किए और इसने तृतीय देशों को निर्यात कीमत संबंधी ब्यौरे नहीं दिए क्योंकि इन्हें आवश्यक नहीं समझा गया ।
  - (iii) उक्त अधिनियम के खंड 9 क की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए जोकि गाट के अनुरूप हो । प्राधिकारी द्वारा की गई खंड 9 क की व्याख्या गाट करार की दृष्टि से सही नहीं है उक्त अधिनियम के अन्तर्गत "राज्य क्षेत्र" शब्द गाट करार द्वारा प्राधिकृत नहीं है । "निर्यातक देश या क्षेत्र" शब्द को निर्यातक देश या निर्यातक क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए । प्राधिकारी का डेनमार्क को निर्यातक देश के रूप में मानना और फिर निर्यातक क्षेत्र में कीमतों का निर्धारण करना सही नहीं है । प्राधिकारी को निर्यातक क्षेत्र में कीमतों का निर्धारण करने का अधिकार तभी है जब जांच निर्यातक क्षेत्र के विरुद्ध चल रही हो ।
  - (iv) प्राधिकारी को अपना यह निष्कर्ष देना चाहिए था (यदि निर्धारण प्रारंभिक निष्कर्षों में किए गए निर्धारण की तरह हो तो) कि ई. यू. को डेनमार्क के क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है और तब डेनमार्क के क्षेत्र में कैटेगिस्टों की कीमतों का निर्धारण किया जाना चाहिए ।
  - (v) गाट करार में "क्षेत्र" शब्द केवल दो स्थानों पर आया है । अनुच्छेद 4.1(11) और 9.1 पर इनमें से कोई भी अनुच्छेद प्राधिकारी को ई. यू. में हुई खपत को डेनमार्क में हुई खपत मानने की शक्तियां प्रदान नहीं करता है । यहां तक कि अनुच्छेद 4.3 में भी "क्षेत्र" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि ऐसे दो या दो से अधिक देशों में घरेलू उद्योग के बारे में विचार करने की शक्तियां प्रदान करता है जहां उनके बाजारों का इस प्रकार से एकीकरण हो गया हो कि उनमें एकल एकीकृत बाजार की विशेषताएं मौजूद हो । इस प्रकार जो देश यूरोपीय संघ में शामिल हैं, उनमें एकल एकीकृत बाजार की विशेषताएं हैं और ई. सी. के समक्ष लायी गयी किसी भी याचिका को अनुच्छेद 4.3 के संदर्भ में घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।"
  - (vi) शब्द "क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो देश का एक हिस्सा होता है । न्यू वेब्टर्स, पैनज्यून इंगलिश डिक्शनरी और भारत के संविधान ने भी इसी प्रकार इस शब्द की व्याख्या की है ।
- (ग) जहां तक यू. एस. ए. में एच डी एस के सामान्य मूल्य का संबंध है, एच टी ए एस से इसकी मांग नहीं की जा सकती है । यू. एस. ए. में सामान्य मूल्य का निर्धारण उक्त देश को अधिसूचित करने तथा यू. एस. ए. में निर्यातक से सूचना प्राप्त करने के बाद विधिवत् शुरू की गई जांच के जरिए किया जा सकता है ।
- (घ) धारा 9क (1) ग (11) के अन्तर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक जांच में प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है । चूंकि एच टी ए एस के विरुद्ध आरोप लगाया गया है इसलिए निर्यातक को इस धारा के अन्तर्गत दिए गए तरीके से आरोप का खण्डन करने की स्वतंत्रता है । यदि घरेलू बिक्री नहीं की गई है तो निर्यातक तीसरे देशों को निर्यात कीमत अथवा उत्पादन लागत दर्शा कर डंपिंग को प्रमाणित नहीं कर सकता है । कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने से आयातक देश में घरेलू उद्योग के पक्ष में बहुत पक्षपात हो जाएगा । तृतीय देशों को किए गए निर्यात की कीमत से संबंधित सूचना न देने के संबंध में निर्यातक ने यह तर्क दिया कि उसने निम्नलिखित दो कारणों से तृतीय देशों को निर्यात कीमत के संबंध में सूचना नहीं भेजी है :—
  - \* यह सूचना आवश्यक नहीं है क्योंकि निर्यातक के पास यह साबित करने के लिए विकल्प उपलब्ध है कि कोई गलत व्यापार नहीं किया गया है, और
  - \* किसी तृतीय देश की कीमत एक "उपयुक्त देश" को किए गए निर्यात की कीमत नहीं है और "तुलनीय प्रतिनिधि कीमत" नहीं है । तृतीय देश को किए गए निर्यात की कीमत संबंधी सूचना देने से निर्यातक के इन देशों में भावी क्रियाकलाप प्रभावित होंगे ।
- (ङ) सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सूची कीमतों के संबंध में, एच टी ए एस ने यह तर्क दिया कि सूची कीमत के इस्तेमाल का गम्भीर परिणाम होने की आशंका है । सूची कीमतें अधिकतर सूची में ही मौजूद होती हैं और लेन-देन की वास्तविक कीमतों में बाजार

परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए व्यापक भिन्नता होती है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष आपत्तिपूर्ण है कि सूची कीमतें प्रचलित वास्तविक कीमतों की संकेतक हैं। उदाहरण के लिए, एच टी ए एस ने 19 आदेशों में से 12 में सूची कीमत से कम पर यूरोपीयन संघ को जेड एन ओ डी एस कैटेलिस्ट की आपूर्ति की और एल टी एस के 13 आदेशों में से 6 आर्डर सूची कीमतों में कम कीमत के हैं।

- (च) दो डमिंग मार्जिन का निर्धारण भ्रामक है। एच टी ए एस ने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने दो सीमाशुल्क शीर्षों के अन्तर्गत सबजेक्ट कैटेलिस्ट में जांच प्रारम्भ नहीं की है। इसके अतिरिक्त ने तर्क दिया कि उसके पास कैटेलिस्ट के लिए इस बात पर निर्भर करते हुए कीमत निर्धारण की कार्यनीति/नीति नहीं है कि कैटेलिस्ट अध्याय 38 के तहत आयात किए जा रहे हैं या अध्याय 98 के तहत हैं। एच टी ए एस ने लगभग एक समान कीमतों पर स्वामित्व कैटेलिस्ट की आपूर्ति की है, चाहे ये प्रारंभिक प्रभार हों अथवा प्रतिस्थापन प्रभार हों।

#### क्षति के बारे में

- (क) दो क्षति मार्जिन का निर्धारण भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि जब याचिकाकर्ता परियोजनाओं को उपर्युक्त कैटेलिस्ट की आपूर्ति करते हैं तब याचिकाकर्ता एक्जिम नीति के अध्याय X के तहत माने गए निर्यात लाभ के लिए पात्र हैं। जब कैटेलिस्ट अध्याय 38 के तहत आयात किया जाता है तो यह लाभ शुल्क तत्व के समान होता है, और इसलिए केवल एक ही क्षति मार्जिन होगा।
- (ख) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है :
- (i) निर्धारित की गई जांच-अवधि मनमानी है और बिना किसी आधार के है।
- (ii) कैटेलिस्ट का जीवन अलग-अलग आपूर्तिकर्ता के मामले में भिन्न है और इसका निर्धारण प्लॉट-डिजाइन द्वारा भी होता है। क्षति पहलू का अध्ययन किया जाना लगभग 3 से 4 वर्षों की एक लम्बी जांच अवधि तक करना पड़ता है।
- (3) प्रारंभिक जांच में प्राधिकारी द्वारा सभी छः प्रकार के कैटेलिस्ट के लिए संचयी रूप से क्षति का निर्धारण भ्रान्तिपूर्ण है। विभिन्न कैटेलिस्टों के लिए विनिर्माण सुविधाएं अलग-अलग हैं और इस के लिए प्राधिकारी के जांच निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक कैटेलिस्ट के लिए अलग ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी सूचना अनदेखी करते हुए यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि न तो यह उपयुक्त है और न ही व्यावहारिक है कि ऐसा तरीका (अलग-अलग कैटेलिस्ट के संबंध में क्षति का निर्धारण करने का तरीका) अपनाया जाए।
- (ग) प्रति-पाटन शुल्क लगाने से कृषक समुदाय के व्यापार हितों पर प्रभाव पड़ेगा।

#### कारणात्मक संबंध के बारे में

- (झ) कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया है। बाजार शेयर का विश्लेषण करते समय क्षति के निर्धारण के लिए एक जांच अवधि के चुनाव और कैटेलिस्ट के लिए अस्थिर मांग पर विचार किया जाना चाहिए। कथित कैटेलिस्टों की आपूर्ति के कुछ टेंडरों में भारतीय उद्योग को चुनिन्दा सूची में लिया भी नहीं गया था और इसलिए, बाजार शेयर की हानि के लिए डेनमार्क से कैटेलिस्ट की आपूर्ति को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। 93.9% (1988) से 68% (जांच अवधि) तक घरेलू उद्योग के बाजार शेयर में गिरावट संबंधी निष्कर्ष में कैटेलिस्ट के आयातों पर लगे प्रतिबन्धों के तथ्य की उपेक्षा की गई है जो 1988 में लगे हुए थे। आई सी आई इंडिया लि. के पास सबजेक्ट में से किसी का भी उत्पादन करने का संयंत्र अथवा क्षमता नहीं है।
- (घ) प्राधिकारी द्वारा जांच
- याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए अनुरोधों की जांच की गई और जहां उपयुक्त समझा गया इसके बाद इन पर विचार किया गया है।
- (ङ) विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तुएं तथा घरेलू उद्योग
5. नियम 2 (घ) के अनुसार "समान वस्तु" का तात्पर्य उस वस्तु से है जो भारत में पाटन हेतु जांच के अधीन वस्तु के समान या हर तरह से समरूप है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर दूसरी वह वस्तु जो हालांकि हर तरह से समान न हो, लेकिन उसके गुण जांच के अधीन वाली वस्तु से मिलते-जुलते हों।
6. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 5 से 9 की पुष्टि करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक संबंधित कैटेलिस्ट, उक्त नियम की परिभाषा के अन्तर्गत डेनमार्क में निर्मित या वहां से निर्यातित संगत उत्प्रेरकों की समान वस्तु है।
- (च) पाटन
7. पाटन के निर्धारण का विरोध करने वाले तर्कों पर इससे ऊपर विचार-विमर्श किया जा चुका है। दिए गए तर्कों का विश्लेषण निम्नानुसार है :
8. निर्यातकों के इस दावे के संबंध में कि एच टी ए एस के प्रतिनिधियों द्वारा मांगे गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए, प्राधिकारी ने नोट किया है कि अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रारंभिक जांच परिणाम में पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श किया गया था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने जो जानकारी निर्यातकों से मांगी थी, निर्यातकों ने वह जानकारी देने से मना कर दिया है और

दूसरी तरफ अधिकारी द्वारा की गई उस गणना की मांग कर रहे हैं जो याचिकाकर्ताओं और निर्यातक द्वारा दी गई गोपनीय जानकारी पर आधारित थी। चूंकि गणना गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है, इसलिए किसी भी हितबद्ध पार्टी (यों) को इसका ब्यौरा नहीं दिया जा सकेगा।

9. सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में एच टी ए एस द्वारा किए गए दावे के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:—

(i) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ताओं ने पाटन के साक्ष्य के तौर पर यू एस ए में एफ ओ बी सूची मूल्य, यूरोप में एफ ओ बी सूची मूल्य, यूरोपीय कंपनियों द्वारा प्राप्त आर्डरों के आधार पर यूरोप में वास्तविक मूल्य और डेनमार्क से निर्यातकों का तृतीय देशों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध कराया था। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रतिपाटन कार्रवाईयों के अंतर्गत प्रारंभिक जाँच कार्रवाई की अधिसूचना में केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त और प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर ही जाँच शुरू होती है जो कि प्रतिपाटन नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों और पूर्व आवश्यकताओं के ही अधीन होती है। इसलिए नियम से यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकारी प्रारंभिक जाँच कार्रवाई के बाद में ही सभी इच्छुक पार्टियों से सभी संगत जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए, एच टी ए एस का यह तर्क कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ई यू को घरेलू बाजार के रूप में मानने के लिए आरंभिक अधिसूचना में या सूचना के लिए किए गए अनुरोध, किसी में भी प्रस्ताव नहीं किया, नियम और प्रक्रियाओं में अमान्य है।

(ii) प्राधिकारी इस बात को नोट करते हैं कि निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई जानकारी मुहैया कराना आवश्यक है। हालांकि निर्यात हमेशा अपने मामले के समर्थन में अपने तर्कों को प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर भी उन्हें तर्क प्रस्तुत करने से पहले प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना मुहैया करानी होगी। निर्यातक इस आधार पर सूचना नहीं देने की बात नहीं कर सकते कि निर्यातक ने जानकारी देना आवश्यक नहीं समझा है। नियम में यह बात नहीं है कि निर्यातक को यह पूर्व-निर्णय लेने का अधिकार है कि प्राधिकारी को किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए किस जानकारी की आवश्यकता है और किसकी नहीं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराकर निर्यातक ने जाँच में सहयोग नहीं किया है और उसने प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने से रोका है कि क्या तीसरे देश की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निकाला जा सकता है अथवा नहीं।

(iii) एच टी ए एस द्वारा ई यू को डेनमार्क के एक क्षेत्र के रूप में विचार के संबंध में दी गई दलील तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में कहाँ भी यह नहीं माना है कि ई यू पर डेनमार्क के एक क्षेत्र के रूप में विचार किया जा सकता है। यहां तक कि सुनवाई के समय भी निर्यातक के विद्वान वकील यहाँ स्पष्ट नहीं कर पाए कि अधिसूचना के किस भाग से यह स्पष्ट होता है कि ई यू डेनमार्क का एक क्षेत्र है। प्राधिकारी ने सिर्फ यह माना है कि ई यू को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक निर्यातक क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि निर्यातक ने यह दर्शाने कि लिए कोई तर्क नहीं दिया है कि ई यू में प्रचलित मूल्यों को निर्यातक के घरेलू बाजार में प्रचलित मूल्यों के रूप में क्यों नहीं विचार किया जा सकता है।

(iv) हालांकि यह समझा जाता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.3 के अन्तर्गत "क्षेत्र" शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है, फिर भी यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो देश पाटनरोधी जाँच के उद्देश्य से एकल एकीकृत बाजार बनाते हैं वे इन एकल एकीकृत बाजारों को घरेलू उद्योग के रूप में मनाते हैं। इस मुद्दे और सामान्य मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से ई यू पर विचार करने के लिए दिए गए तर्क पर प्रारंभिक निष्कर्षों में चर्चा की गई है और उसके बाद कोई पर्याप्त तर्क नहीं उठाए गए हैं। हालांकि यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी ने ई यू को डेनमार्क के एक क्षेत्र के रूप में माना है तथापि यह आदेश ई यू को सामान्य मूल्य-निर्धारण के सीमित उद्देश्य से एक क्षेत्र के रूप में मानता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि निर्यातक अपने तर्क पेश करने के लिए स्वतंत्र है तथापि निर्यातक का पहला दायित्व प्राधिकारी द्वारा निवेदित सूचना देने का है ताकि प्राधिकारी द्वारा एक उपयुक्त निर्णय किया जा सके। परन्तु, वर्तमान मामले में एच टी ए एस ने इच्छा व्यक्त की है कि तीसरे देशों को निर्यात मूल्य के ब्यौरे प्रकट न किए जाएँ। सूचना प्रस्तुत नहीं करने के लिए निर्यातक द्वारा दिए गए कारणों को माना नहीं जा सकता, यद्यपि निर्यातक के पास पसन्द उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, यह मानने के लिए निर्यातक द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए कि तीसरे देशों को निर्यात मूल्य तुलनीय प्रतिनिधिक मूल्य नहीं होगा या किसी भी देश को एक उपयुक्त देश के रूप में नहीं माना जा सकता। वास्तव में, निर्यातक ने बिना किसी आधार के तर्क दिया है कि तीसरे देशों के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण से इन देशों में उसके भावी व्यापारिक क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ सकता है।

10. एच डी एस केटेलिस्ट के सामान्य मूल्य के संबंध में प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं की भारत में एच टी ए एस ने केटेलिस्ट की आपूर्ति की है जिसका उत्पादन इसकी सहायक कम्पनी द्वारा किया गया था। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि निर्यातक ने प्रस्तावली अनुक्रिया के उत्तर में अपने निम्नलिखित संयंत्रों के नाम और पतों के विवरण लिए हैं :

\* हल्डोर टोप्सो ए/एस, डेनमार्क

\* हल्डोर टोप्सो, ईक, टेक्सास, यू एस ए

कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट से आगे और पता चला है कि हल्डोर टोप्सो ईक, हल्डोर टोप्सो ए/एस की 100% स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी है।

11. उपरोक्त की दृष्टि में निर्यातक का यह दावा कि इस कैटेलिस्ट के सामान्य मूल्य के ब्यौरे देने की उम्मीद नहीं की जा सकती, को नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा निवेदित सूचना प्रस्तुत नहीं की है इस प्रकार उसने जांच में पर्याप्त रूप में बाधा पहुँचाई है।
12. एच डी एस कैटेलिस्ट के संबंध में प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि निर्यातक से उन मूल्यों के बारे में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था, जिन वास्तविक मूल्यों पर उसने व्यापार का लेन देन किया था, जो कि निर्यातक द्वारा नहीं भेजी गई थी। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि मूल्य सूची सौदे के मूल्यों को निर्दिष्ट करती है और उसके विपरीत कोई (साक्ष्य) नहीं है। प्राधिकारी की टिप्पणी है कि निर्यातक ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए उन मूल्यों को प्रकट नहीं किया है जिनके आधार पर उसने तर्क प्रस्तुत किए हैं। अतः प्राधिकारी ने मूल देश में प्रचलित मूल्यों के संबंध में उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य ठीक ही निर्धारित किया है।
13. दो डम्पिंग मार्जिनों का निर्धारण करने वाले तथा केवल सीमा शुल्क शीर्ष के अंतर्गत आयातों के विरुद्ध प्रतिपादन जांच की शुरूआत करने के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया कि संबंधित कैटेलिस्टों का आयात दो अलग-अलग तथा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट सीमाशुल्क शीर्षों के तहत किया जा रहा है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है जिस सीमाशुल्क शीर्ष के अंतर्गत उत्पाद की निकासी की गई जैसा कि प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित है, उससे वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है कि सीमाशुल्क शीर्षों को लिखने का प्रयोजन संबंधित वस्तुओं की जानकारी को सुगम बनाना है न कि जांच के कार्य क्षेत्र को समिति करना। दो सीमाशुल्क शीर्षों के तहत इन कैटेलिस्टों के आयात की अनुमति अलग और भिन्न स्थितियों में दी जाती है। निर्यातक का यह तर्क कि निर्यात की कीमत वह कमोबेश वही है चाहे आपूर्तियाँ प्रारंभिक हों अथवा प्रतिस्थापन हो, वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी ने दोनों शीर्षों के तहत क्लीयरेंस के मामले में भिन्न-भिन्न डंपिंग मार्जिन पाए हैं।
14. उपर्युक्त बातों को देखते हुए तथा इच्छुक पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी डंपिंग का निर्धारण करने के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनाई गई कार्य पद्धति की पुष्टि करते हैं। डंपिंग मार्जिन निम्नानुसार है :

कैटेलिस्ट का नाम	डंपिंग मार्जिन (प्रतिशत निर्यात मूल्य)	
	सी एच 38	सी एच 98
हाइड्रोडीसल्फराइजेशन कैटेलिस्ट (एच डी एस)	32.61	85.19
जिंक आक्साइड डीसल्फराइजेशन कैटेलिस्ट (जैडएनओ)	76.06	90.34
हाई टैम्परेचर शिफ्ट कैटेलिस्ट (एच टी एस)	97.04	153.97
लो टैम्परेचर शिफ्ट कैटेलिस्ट (एल टी एस)	100.00	113.90
सैकेंडरी रिफारमिंग कैटेलिस्ट (एस आर)	शून्य	152.71
मैथनेशन कैटेलिस्ट (मेथ)	134.74	134.74

#### छ. क्षति

15. घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों के विरोध में दिए गए तर्कों पर ऊपर विचार-विमर्श किया गया है। दिए गए तर्कों के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :
16. दो क्षति मार्जिनों का निर्धारण करने के बारे में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को उपलब्ध माने गए निर्यातों के लाभों पर विचार करने के बाद अध्याय 98 के तहत की गई निकासियों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण करने हेतु उचित बिक्री कीमत निकासी है। एच टी ए एस के इस तर्क में दम है कि दो उचित बिक्री कीमतें होनी चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अध्याय 38 और 98 के अंतर्गत की गई निकासियों अलग-अलग परिस्थितियों में गई हैं तो दो क्षति मार्जिन निकालना उचित होगा।
17. जांच अवधि का प्रयोग डंपिंग निकालने के लिए किया जाता है। जांच अवधि सहित 3 से 5 वर्षों की लंबी अवधि का प्रयोग घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानना होगा कि कैटेलिस्टों की आयु में काफी भिन्नता होती है जिसके परिणामस्वरूप मांग के स्वरूप में उतार-चढ़ाव आता है। तथापि, निर्यातक का यह दावा कि विनिर्माण संबंधी सुविधाएं प्रतिच्छादित नहीं होती, जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, वास्तव में सही नहीं है क्योंकि स्थान पर की गई जांच के दौरान यह पाया गया था कि याचिकाकर्ताओं की विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, उदाहरणार्थ सुखाने और फोर्मिंग क्षमताएं सांझा हैं। चूंकि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन करना होता है इसलिए इस बारे में केवल घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक ही संगत हैं।
18. घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में प्रारंभिक निष्कर्ष घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले केवल किसी एक ही पैरामीटर पर निर्भर नहीं करते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, कीमत, स्टॉक, लाभप्रदता आदि। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न संकेतक सामूहिक और संघयी आधार पर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। हितबद्ध पार्टियों के इन तर्कों को कि कुछेक कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, नकारा जाना आवश्यक है।

19. उपर्युक्त को देखते हुए और हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह बताने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति होने के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

#### ज. कार्य-कारण संबंध

20. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति डम्प आयातों के कारण हुई है। जहाँ तक जांच अवधि में 1992 की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का संबंध है, यह तर्क कि 1998 में आयात प्रतिबन्धित थे (जिसके कारण आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ गया), से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि डम्पिंग कीमतों पर कैटेलिस्ट का आयात से भारतीय बाजार में इसकी कीमतें कम हो गई और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें ऐसे स्तर तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे कि वह अपने उत्पादन की पूरी लागत वसूल कर एक उचित लाभ कमाने से वंचित रह गया जिस पर किसी हितबद्ध पार्टी(यों) द्वारा विचार भी नहीं उठाया गया है। प्राधिकारी ने यह बात नोट किया कि अनुसंधान और विकास कार्य किसी भी उद्योग का विशेषकर वर्तमान जैसे उद्योग के मामले में एक अनिवार्य और भिन्न हिस्सा है, कोई भी उद्योग अपने अनुसंधान और विकास प्रयास जारी नहीं रख सकता, यदि उसके कार्य घाटे में चल रहे हों।
21. उपर्युक्त तथा हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि डम्प आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

#### अंतिम निष्कर्ष

22. उपर्युक्त बातों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :
- \* डेनमार्क मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु कैटेलिस्ट का भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्यों पर निर्यात किया गया है ;
  - \*\* घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ;
  - \*\*\* घरेलू उद्योग को यह क्षति डेनमार्क मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु कैटेलिस्ट के निर्यात के कारण हुई है।
23. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच-परिणामों की पुष्टि करते हुए डेनमार्क मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु कैटेलिस्ट के सभी आयातों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चित प्रति पाटन शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं :

कैटेलिस्ट का नाम	शुल्क की राशि (रु. प्रति लीटर)	
	जब अध्याय 38 के तहत आयात किया गया	जब अध्याय 98 के तहत आयात किया गया
हाइड्रोडीसल्फरीजेशन कैटेलिस्ट (एच डी एस)	36.23	121.59
जिंक आक्साइड डी सल्फरीजेशन कैटेलिस्ट (जैड एन ओ)	शून्य	शून्य
हाई टैम्परेचर शिफ्ट कैटेलिस्ट (एच टी एस)	25.64	87.89
लो टैम्परेचर शिफ्ट कैटेलिस्ट (एल टी एस)	52.61	117.50
सैकेन्डरी रिफार्मिंग कैटेलिस्ट (एस आर)	शून्य	266.49
मैथानेशन कैटेलिस्ट (मिथ)	215.46	215.46

24. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी दिनांक 7-5-1996 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।
25. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार इस आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में की जा सकेगी।

रत्ति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 1998

**FINAL FINDINGS**

**Subject: Anti dumping investigation concerning Imports of certain catalysts from Denmark - Final Findings**

**ADD/IW/39/95-96:-** Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

**A. PROCEDURE**

1. The Procedure described below has been followed:
  - i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification no. ADD/IW/39/95-96 dated the 7th May, 1997 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
  - ii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to known interested parties who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
  - iii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of Denmark in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;
  - iv) The Authority held an oral hearing on 8th July, 1997 to hear views orally. All the parties attending the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals.
  - v) The Authority made available the public file to the interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted to the Authority by various interested parties. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file;
  - vi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;



- vii) Subsequent to the appointment of new Designated Authority by the Central Government on 17th Dec., 1997, all interested parties were advised vide letter dated 22nd Dec., 1997 to indicate if they would like to explain orally the submissions made by them, which were already on record, in accordance with Rule 6(6). The interested parties were informed that they could appear before the Authority on 2nd Jan., 1998, if so desired to explain their case orally.
- viii) The Authority held an oral hearing on 2nd Jan., 1998. It was clarified that no new issues could be brought up and that the arguments should be limited to issues presented at the hearing on 8th July, 1998. No written statements were taken on record.
- ix) On 2nd Jan., 1998, the learned counsel for HTAS desired to know whether the Central Government had granted extension of time period. It was clarified to all the interested parties present on 2nd Jan., 1998 that the Authority was hearing orally within the time limits extended by the Central Govt.
- x) The investigations have been concluded within the time limit extended by the Central Government, i.e., 5th Jan., 1998.

## **B. PETITIONER'S VIEWS**

### **2. The petitioner raised the following arguments:**

- a) In the absence of sales in the home market, the appropriate price to consider is the price the exporter has charged in the European Union (EU).
- b) Consideration of EU as a territory by the Authority is appropriate. It is appropriate to consider EU as a territory which is virtually a quasi-sovereign entity, the constitution of which provides free flow of goods within its bounds and has the power to direct removal of all impediments and is now contemplating a common currency and, in view of the following:
  - Article XII of the WTO Agreement covers any State or separate customs territory;
  - The EU is recognised as a single unit for various purposes, such as EU itself is treated as a member. Annexure 3 to WTO Agreement inter-alia provides that for purposes or certain reviews, the EU will be counted as one;
  - While construing the law for determination of normal value, the principles of purposive interpretation to the provisions of the law should be applied.
  - The statute confers upon the Central Govt. a power to impose a fiscal levy to protect the Indian industry, and, therefore, leaves considerable latitude to the Central Govt. to adopt one or other method of determination.
  - The expression "territory" cannot be limited to a geographical area contained within a country, and interpretation drawn from the Constitution of India would not be appropriate. It would be inappropriate to apply universal meaning to the word, and the word must be construed with reference to its context and not in isolation.

- The provisions of the law are a direct fallout of the GATT treaty whose objective is to establish domestic price for comparison with export price. EU is a cohesive trade unit, and is, for more than one purpose treated as a single unit.
- c) The price HTAS has charged in the EU and to the Indian customers establishes that it has dumped catalyst in India.
- d) The prices charged by the other European manufacturers also establish that the exporter dumped the subject catalyst in India.
- e) The dumping by HTAS has caused material injury to the Indian industry. The Indian industry was selling below the cost of production and their capacity utilisation suffered.

**C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

3. The views expressed by the exporter, Haldor Topsoe A/S (referred to as HTAS hereinafter) and other interested parties are as under:

**On dumping:**

- a) The Authority was requested to furnish the details of normal value and export price used in the calculation of dumping margin.
- b) The finding that EU is the exporting territory for determination of normal value is legally incorrect, in view of the following:
  - i) The Authority did not propose to treat EU as the domestic market for determination of normal value either in the Initiation notice or in the questionnaire (Request for Information). The Authority has violated the principles of natural justice by making the determination without notice.
  - ii) HTAS treated Denmark as the exporting country and submitted that there were no sales in the home market. The exporter, therefore, furnished details of cost of production and did not furnish details of export price to third countries as the same were considered to be not necessary.
  - iii) Section 9A of the Act supra has to be assigned such interpretation as is GATT compatible. Interpretation of Section 9A by the Authority is incorrect in view of the GATT Agreement. The word "territory" appearing under Section 9A of the Act supra is not authorised by GATT Agreement. The word "exporting country or territory" should be read as exporting country or exporting territory. The Authority is not correct in treating Denmark as the exporting country and then determining prices in the exporting territory. The Authority is entitled to determine prices in the exporting territory only when the investigations are against exporting territory.
  - iv) The Authority should have given its finding (if the determination is to be made as was done in the preliminary findings) that EU could be

considered as territory of Denmark and then determined the price of the catalysts in the territory of Denmark.

- v) The word "territory" appears at only two places in the GATT agreement, Article 4.1 (ii) and 9.1. None of these articles empower the Authority to treat the consumption in the EU as the consumption in Denmark. Even Article 4.3, which empowers consideration of domestic industry in two or more countries in case their markets have reached such integration that they have the characteristics of a single unified market, does not use the word "territory". Thus the countries which form the EU have the characteristics of a single unified market and hence any petition brought before the EC has to satisfy the requirements of domestic industry with reference to Article 4.3.
- vi) The word "territory" means an area forming part of a country. New Webster's, Penguin English Dictionary and the Constitution of India have defined the word similarly.
- c) With regard to normal value of HDS in USA, the same cannot be demanded from HTAS. The normal value in USA can be determined only by an investigation properly initiated after notifying the said country and obtaining the information from the exporter in USA.
- d) With regard to the determination of normal value under Section 9A(1)(c)(ii), the view taken by the Authority in the preliminary findings is erroneous. Since an allegation has been made against HTAS, the exporter is at liberty to rebut the allegation by means which are provided under the Section. If there are no domestic sales, the exporter can establish no dumping by showing either the export price to third countries or the cost of production. Any other view will render strong bias in favour of domestic industry in the importing country.

With regard to non-submission of information relating to export price to third countries, HTAS argued that it has not supplied information relating to export price to third countries for the following two reasons:

- the information is not required since there is a choice available to the exporter to prove by other means that there is no unfair trade; and
  - price to any third country is not a price to an "appropriate country" and is not a "comparable representative price". The information on export price to third countries will affect the exporter's future trading activities in these countries.
- e) With regard to list prices for determination of normal value, HTAS argued that use of list prices is fraught with serious repercussions. The list prices exist mostly in the list only and the actual transaction prices vary widely depending on the market conditions. The conclusion of the Authority that the list prices are indicative of actual prices prevailing is erroneous. To illustrate, HTAS supplied ZnODS catalyst in EU at less than the list price in 12 out of 19 orders, and 6 out of 13 orders of LTS are below list prices.

- f) Determination of two dumping margin is erroneous. HTAS argued that the Authority did not initiate investigations into the subject catalysts under the two custom heads. Further, the exporter argued that it did not have pricing strategy/policy for the catalysts depending on whether the catalysts are being imported under Chapter 38 or under 98. HTAS supplied proprietary catalysts at more or less the same prices, whether these were initial or replacement charge.

**On Injury:**

- a) Determination of two injury margin is erroneous, as the Authority has not taken into account the fact that the petitioners are entitled to Deemed Export benefit under Chapter X of the EXIM policy when the petitioners supply the said catalysts to projects. The benefit is equal to the duty element when the catalyst is imported under Chapter 38, and therefore, there will be only one injury margin.
- b) There is no material injury to the domestic industry, in view of the following:
- i. The period of investigation determined is arbitrary and without any basis.
  - ii. Life of catalysts differs from supplier to supplier and is also determined by plant design. Injury aspect has to be studied over a very long period of investigation of about 3 to 4 years.
  - iii. The assessment of Injury cumulatively for all the six types of catalysts by the Authority in the preliminary findings is erroneous. The manufacturing facilities for the different catalysts are different and the findings of the Authority on this account are without any evidence. The petitioners had provided separate details for each catalyst. Disregarding such information furnished by the petitioners and concluding that it is neither appropriate nor feasible to adopt such a course (of assessing injury in respect of individual catalyst) is not warranted.
- c) Imposition of anti-dumping duty will affect the larger interests of the farming community.

**On causal link:**

Causal relationship has not been established. Choice of a wrong period of investigation for assessment of injury and fluctuating demand for catalysts have to be considered while analysing the market share. The Indian industry was not even short-listed in some of the tenders to supply the said catalysts, and, therefore, the loss of market share cannot be attributed to the supply of catalysts from Denmark. The finding of the decline in market share of the domestic industry from 93.9% (1988) to 68% (investigation period) overlooks the fact of restrictions placed on imports of catalysts that prevailed in 1988. ICI India Ltd. does not have the plant or capability to produce any of the subject catalysts.

**D. EXAMINATION BY AUTHORITY**

4. The submissions made by the petitioners, exporters, importers and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, have been dealt hereinafter.

**E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, LIKE ARTICLES AND DOMESTIC INDUSTRY**

5. Under Rule 2(d) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
6. The Authority confirms paras 5 to 9 of the preliminary findings and confirms that each of the subject catalysts produced by the domestic industry is a like article to the respective subject catalysts originating in or exported from Denmark within the meaning of the rules supra.

**F. DUMPING**

7. The arguments raised opposing determination of dumping have been discussed hereinabove. Analysis of the arguments raised is as under:
8. With regard to the exporters contention that details of normal value and export price requested by the representatives of HTAS ought to have been furnished, the Authority notes that the methodology adopted was discussed in sufficient detail in the preliminary findings. The Authority further notes that the exporter has declined to furnish the information requested by the Authority and, on the other hand, desired the calculations done by the Authority, which were based on the confidential information furnished by the petitioners and the exporter. Since the calculations were based on the information furnished on confidential basis, no details can be furnished to any interested party(ies).
9. With regard to the contentions raised by HTAS on determination of normal value, the position is as under:
- i) The Authority had clearly mentioned in the Initiation Notification that the petitioners had provided, as evidence of dumping, fob list price in USA, fob list price in Europe, actual prices in Europe on the basis of orders procured by European companies and export price of the exporters from Denmark to third countries. It needs to be appreciated that under the anti-dumping proceedings, an initiation notification merely starts an investigations based on sufficient and prima-facie evidence submitted by the petitioners subject only to the conditions and pre-requisites mentioned under Rule 5 of the Anti-dumping Rules. The law, therefore, envisages that the Authority is authorised to collect all the relevant information from the interested parties subsequent to the initiation notification only. The argument of HTAS that the Authority did not propose to treat EU as the domestic market for determination of normal value either in the initiation notice or in the request for information is, therefore, untenable in law and procedures.
- ii) The Authority notes that the exporter is required to furnish the information as is deemed necessary by the Authority. While the exporter can always advance his arguments to support his case, it is

required to furnish the information requested by the Authority before advancing any argument. The exporter cannot plead non-submission of information on the grounds that the information is not considered necessary by the exporter. It is not conceived in law that the exporter has a right to pre-decide as to what information is necessary and what is not for the Authority to arrive at a decision. The Authority notes that by not providing the desired information, the exporter has not co-operated in the investigations and has prevented that Authority from analysing whether normal value can be established on the basis of export price to third country.

- iii) The argument of HTAS with regard to consideration of EU as a territory of Denmark is not based on facts. The Authority has not held anywhere in the preliminary findings that EU could be considered as a territory of Denmark. Even at the time of hearing, the learned counsel of the exporter could not elaborate as to which portion of the notification leads to this interpretation that EU is a territory of Denmark. The Authority has merely held that EU can be considered as an exporting territory for determination of normal value. The Authority notes that the exporter has not advanced any argument to show as to why the prices prevailing in the EU cannot be considered as the prices prevailing in the domestic market of the exporter.
- iv) Though it is appreciated that the word "territory" has not been used under Article 4.3 of the Anti-dumping agreement, yet it is abundantly clear that the countries which form a single unified market, for the purpose of anti-dumping investigations, consider these single unified markets as the domestic industry. This issue and the rationale behind considering EU for the purpose of determination of normal value has been discussed in the preliminary findings and no substantive arguments have been raised thereafter. Even though it has been contended that the Authority has considered EU as a territory of Denmark, the order categorically considers EU as an exporting territory for the limited purpose of determination of normal value.

Under the circumstances, the Authority holds that while the exporter is at a liberty to advance his argument, the primary responsibility of the exporter is to furnish information requested by the Authority so that an appropriate decision can be made by the Authority. In the instant case, however, HTAS has preferred not to disclose the details of the export price to third countries. The reasons advanced by the exporter for not furnishing the information cannot be appreciated. Further, no arguments have been advanced by the exporter for holding that export price to third countries would not be a comparable representative price or no country can be considered as an appropriate country. In fact, the exporter has, without any basis, argued that disclosure of information with regard to third countries may affect its future trading activities in these countries.

10. With regard to normal value of HDS catalyst, the Authority notes that HTAS supplied the catalysts in India, which were produced by its subsidiary. The Authority notes that the exporter, in response to the Questionnaire

Response, has furnished details of the following plants, while answering the names and addresses of its plants:

- Haldor Topsoe A/S, Denmark
- Haldor Topsoe, Inc., Texas, USA

It is further found from the annual report of the company that Haldor Topsoe, Inc. is a 100 percent owned subsidiary of Haldor Topsoe A/S.

11. In view of the above, the claim of the exporter that it cannot be expected to furnish details of normal value of this catalyst cannot be appreciated. The Authority notes that the exporter has not furnished information requested by the Authority, thus impeding the investigations significantly.
12. With regard to normal value of HDS catalyst, the Authority notes that the exporter was requested to furnish factual information about the prices at which business was transacted by it, which were not supplied by the exporter. The information available with the Authority shows that list prices are indicative of the transaction prices and there was no evidence to the contrary. The Authority notes that the exporter, even while advancing his argument, has not disclosed the prices on the basis of which the argument has been advanced. The Authority has, therefore, rightly determined the normal value on the basis of the best information available to it regarding the prices prevailing in the country of origin.
13. With regard to determination of two dumping margins and initiation of investigations against imports under one custom head only, the Authority notes that the subject catalysts are being imported under two distinct and clearly identified Custom heads. The Authority further notes that custom head under which the product is cleared as mentioned in the Initiation notification does not alter the factual position, as it has been abundantly made clear in the preliminary findings that the purpose of writing custom heads is to facilitate understanding of the subject goods and not to limit the scope of the investigations. Import of these catalysts under the two custom heads are being allowed under separate and distinct conditions. The argument of the exporter that its export price has been more or less the same whether the supplies were initial or replacement charge is factually incorrect, as the Authority has found different dumping margins in case of clearances under the two heads.
14. In view of the foregoing and after considering the arguments raised by interested parties, the Authority confirms the methodology adopted in the preliminary findings with regard to determination of dumping. The dumping margins are as follows:

Name of the catalyst	Dumping margin ( % of export price )	
	Ch 38	Ch 98
Hydrodesulphurisation Catalyst (HDS)	32.61	85.19
Zinc Oxide Desulphurisation Catalyst (ZnO)	76.06	90.34
High Temperature Shift Catalyst (HTS)	97.04	153.97
Low Temperature Shift Catalyst (LTS)	100.00	113.90

Secondary Reforming Catalyst (SR)	nil	152.71
Methanation Catalyst (Meth)	134.74	134.74

G. **INJURY**

15. The arguments raised opposing preliminary findings with regard to the injury to the domestic industry has been discussed above. The position with regard to the arguments raised is as under:
16. With regard to determination of two injury margins, the Authority has worked out fair selling price for determination of injury margin for clearances under Chapter 98 after considering the benefit of deemed exports available to the domestic industry. There is force in the argument of HTAS that there should be two fair selling prices and in view of the fact that the clearances under Chapter 38 and 98 are under different conditions, it would be appropriate to work out two injury margins.
17. The investigation period is used to work out dumping. A longer period of three to five years including the investigation period is used to assess the injury to domestic industry. It is appreciated that life of catalysts varies significantly resulting in fluctuating demand pattern. However, contention of the exporter that the manufacturing facilities do not overlap is factually incorrect in so far as the petitioners are concerned, as it was found during the spot investigations that the manufacturing facilities of the petitioners, for instance, drying and forming capacities, are common. Since the Authority is required to assess the injury to the domestic industry, the factors affecting the domestic industry only are relevant in this regard.
18. The preliminary findings with regard to the injury to the domestic industry is not based on any single parameter affecting the domestic industry, such as production, capacity utilisation, sales, selling prices, stocks, profitability, etc. The Authority has clearly held in the preliminary findings that various indicators relating to the domestic industry, collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury. The arguments of the interested parties that some of the factors do not show injury to the domestic industry deserves to be ignored.
19. In view of the above and after considering the arguments raised by the interested parties, the Authority holds that there is sufficient evidence to suggest that the domestic industry has suffered material injury. The Authority, therefore, confirm the preliminary findings with regard to the injury to the domestic industry.

H. **CAUSAL LINK**

20. The material injury has been caused to the domestic industry by the dumped imports. The argument that imports in 1988 were restricted (because of which the market share of the imports increased) does not alter the position in as much as the market share of the domestic industry declined in the investigation period as compared to 1992. Furthermore, the findings of the Authority that the import of catalysts at dumping prices resulted in price underselling in the Indian market and forced the domestic industry to reduce the prices to such an extent that the domestic industry



was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit have also not been disputed by any interested party(ies). The Authority notes that the Research & Development is an integral and essential part of an industry, particularly an industry like the present. No industry can afford to continue its R&D efforts in case its operations are at a loss.

21. In view of the above and after considering the arguments raised by the interested parties, the Authority holds that there is sufficient evidence to suggest that material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

### I. FINAL FINDINGS

22. The Authority, after considering the foregoing, concludes that:
- The subject catalysts originating in or exported from Denmark have been exported to India below their normal value;
  - the domestic industry has suffered material injury;
  - the injury has been caused to the domestic industry by the exports of the subject catalysts originating in or exported from Denmark.
23. The Authority confirms the preliminary findings and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on all imports of subject catalysts originating in or exported from Denmark at the rates specified below:

Name of the catalyst	Amount of Duty (Rs. per ltr.)	
	When Imported under Chapter 38	When Imported under Chapter 98
Hydrodesulphurisation Catalyst (HDS)	36.23	121.59
Zinc Oxide Desulphurisation Catalyst (ZnO)	nil	nil
High Temperature Shift Catalyst (HTS)	25.64	87.89
Low Temperature Shift Catalyst (LTS)	52.61	117.50
Secondary Reforming Catalyst (SR)	nil	266.49
Methanation Catalyst (Meth)	215.46	215.46

24. Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 7.5.1996.
25. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

3161/98-3.

